UP में केन प्राइस नहीं बदला

राज्य सरकार ने SAP का ऐलान किया, मिलों को कीमत पर ऐतराज

[मनमोहन राय & श्रेया राय *लखनऊ & नई दिल्ली*]

उत्तर प्रदेश में शुगर इंडस्ट्री बंद करने के मिलों के फैसले के 24 घंटे के भीतर राज्य सरकार ने गन्ना के लिए स्टेट एडवाइज्ड प्राइस (एसएपी) का ऐलान कर दिया। इसे पिछले साल के बराबर यानी 280 रुपये प्रति क्विंटल रखा गया है।

यूपी की शुगर इंडस्ट्री और केन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी राहुल भटनागर ने बताया, 'शुरुआती वेरायटी के लिए दाम 290 रुपये प्रति क्विंटल रखा गया है, जनरल के लिए 280 रुपये प्रति क्विंटल और रिजेक्टेड वेरायटी के लिए 275 रुपये प्रति क्विंटल है। ये रेट पिछले शुगर सीजन के बराबर है।' इससे पहले इकनॉमिक टाइम्स ने खबर दी थी कि राजनीतिक फायदों को ध्यान में रखते हुए गन्ने की कीमत पर फैसले से राज्य की 35,000 करोड़ की यह इंडस्ट्री शटडाउन का फैसला कर सकती है।

माना जा रहा है कि एसएपी पर फैसले में तेजी बरेली में 21 नवंबर को होने वाली समाजवादी पार्टी की रैली को ध्यान में रखते हुए दिखाई गई है। बरेली में गन्ने की बहुत ज्यादा खेती होती है।

हालांकि, शुगर इंडस्ट्री ने बंदी जारी रखने का फैसला किया है और वह 2013-14 wशुगर सीजन में काम नहीं करेगी। इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन के डायरेक्टर जनरल अविनाश वर्मा ने बताया, 'गन्ना किसानों का 2012-13 सीजन में 2,400 करोड़ के बकाए का भुगतान अगले सीजन में किया जाना है। हमारी भुगतान क्षमता कम है और सरकार ने पिछले साल के बराबर ही गन्ने की कीमत का ऐलान कर डाला है। इससे मार्च-अप्रैल 2014 में गन्ने का बकाया 12,000-13,000 करोड़ हो जाएगा। यह एसएपी व्यावहारिक नहीं है और यूपी की मिलों की 225 रुपये प्रति क्विंटल भुगतान क्षमता से काफी ज्यादा है। 2013-14 में गन्ने की पेराई शुरू करने के लिए इस कीमत पर बैंकों को लोन के लिए राजी करना बेहद मुश्किल होगा।'

> शुगर इंडस्ट्री बंद करने के मिलों के फैसले के 24 घंटे के भीतर उत्तर प्रदेश की सरकार ने गन्ना के लिए स्टेट एडवाइज्ड प्राइस का ऐलान कर दिया। इसे पिछले साल के बराबर यानी 280 रुपये प्रति क्विंटल रखा गया है। इस पर शुगर मिल मालिकों को ऐतराज है

सरकारी अधिकारियों का कहना है कि मिलें अब भी काम शुरू नहीं कर रही हैं। अब सरकार को मिलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने पर मजबूर होना पड़ेगा।

भटनागर ने बताया, 'अगर मिलें पेराई शुरू नहीं करती हैं, तो हम कानूनी रास्ता अख्तियार करेंगे। कानूनी प्रावधानों के तहत सरकार को मिल का काम तय समय पर शुरू करवाने का अधिकार है।'

उन्होंने बताया कि एसएपी का निर्धारण गन्ने की फसल पर बढ़ते खर्च, इसे शुगर में बदलने का खर्च और चीनी की सुस्त कीमतों को ध्यान में रखकर किया गया है। केन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी राहुल भटनागर ने कहा, 'सरकार ने गन्ने की कीमत का ऐलान कर अपना काम कर दिया है और अब गन्ना मंगाकर पेराई शुरू करने की जिम्मेदारी मिलों की है।' उन्होंने बताया कि यूपी में शुगर मिलों की गन्ना खरीद से किसानों को 22,500 करोड़ रुपये का फायदा होगा।

हालांकि, राज्य सरकार ने मिलों को भी कुछ सहूलियत देने की कोशिश की है। सरकार ने मिलों के लिए गन्ने की खरीद पर लगने वाला परचेज टैक्स (2 रुपये प्रति क्विंटल) खत्म करने का फैसला किया है।

कंपनियों के शेयरों में 20% तक की मजबूती

राहत पैकेज की उम्मीद से शुगर स्टॉक्स में मिठास

[ईटी ब्यूरो *मुंबई*]

चीनी कंपनियों के शेयरों की कीमत में बुधवार को 20 फीसदी तक तेजी आई। दरअसल, बाजार में चर्चा है कि सरकार ने एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई है। इसमें उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र की संकटग्रस्त शुगर इंडस्ट्री के लिए राहत पैकेज पर चर्चा होने की उम्मीद है। राहत पैकेज में उनके लिए बैंकों से इंटरेस्ट फ्री लोन हो सकता है।

महाराष्ट्र के बाद भारत के दूसरे सबसे बड़ी चीनी उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश की बहुत सी चीनी मिलों ने गन्ने की पेराई करने से मना कर दिया है। गन्ने की सही कीमत को लेकर राज्य सरकार और उनके बीच गतिरोध बना हुआ है। उत्तर प्रदेश की चीनी मिलों ने कहा है कि वह सिर्फ 225 रुपये प्रति क्विंटल का रेट दे सकती हैं, जबकि किसान 320 रुपये प्रति क्विंटल का रेट मांग रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछले साल गन्ने की कीमत 280 रुपये प्रति क्विंटल तय की थी।

बुधवार को चीनी कंपनियों के शेयरों की कीमत में भले ही तेजी आई हो, लेकिन एनालिस्ट्स इनवेस्टर्स को सावधानी बरतने की सलाह दे रहे हैं। आईआईएफएल के रिसर्च हेड अमर अंबानी कहते हैं, 'चीनी कंपनियों के शेयर गन्ने की ऊंची कीमत को लेकर उत्तर प्रदेश की चीनी मिलों में शटडाउन को लेकर आ रही खबरों पर रिएक्ट करते रह सकते हैं। लेकिन हमारी सलाह यह है कि इनवेस्टर्स को फिलहाल चीनी कंपनियों के शेयरों से बचना चाहिए।' उत्तर प्रदेश की चीनी मिलों ने गन्ने की कीमत पर राज्य सरकार को क्लोजर नोटिस भेजा है। इस पर ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि शुगर क्राइसिस को लेकर बुधवार को देर रात फाइनेंस मिनिस्टर पी चिदंबरम, एग्री मिनिस्टर शरद पवार और सिविल एविएशन मिनिस्टर अजित सिंह सहित कई सेंट्रल मिनिस्टर्स के ग्रुप की मीटिंग हो सकती है। देश के दो बड़े चीनी उत्पादक राज्यों महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश की चीनी कंपनियों ने अक्टूबर में शुरू होने वाले नए क्रॉप सीजन में गन्ने की पेराई शुरू नहीं की है।

उनका कहना है कि गन्ने का बकाया बढ़ता जा रहा है और उनके पास बहुत सा स्टॉक पड़ा हुआ है।

सावधान! निवेशक

- उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र की संकटग्रस्त शुगर इंडस्ट्री के लिए राहत पैकेज पर चर्चा करने के लिए सरकार ने एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई है। इसमें कंपनियों को बैंकों से इंटरेस्ट फ्री लोन मिलने की उम्मीद है
- चीनी कंपनियों के शेयरों की कीमत में भले ही तेजी आई हो, लेकिन एनालिस्ट्स इनवेस्टर्स को सावधानी बरतने की सलाह दे रहे हैं

✓ Economic Times 21/11/13